प्रभात खबर 13
रांची, बुधवार, 23 जून, 2010

मनातू वाया भकासी... बरास्ता छतरपुर

अरविंद

भकासी जाते हुए अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज द्वारा दिसंबर 2003 में लिखे रपट का चर्चित अंश याद आता है कि लेस्लीगंज में दर्जन भर और भकासी में भुखमरी से हुई चार से अधिक मौतों पर तत्कालीन जिला कलक्टर ने ग्रामीणों को कहा था कि 'बारिश इसलिए नहीं हुई, क्योंकि तुमने पूरे मन से प्रार्थना नहीं की थी.' इस निर्मम टिप्पणी से तब के जिलाधिकारी की संवेदनहीनता ही पता चलती है. मगर तब के जिलाधिकारी हो या आज के, वे भूख से होनेवाली मौतों की अवधारणा को खारिज करते हैं, और ऐसी कोई जवाबदेही भी नहीं लेते.

भकासी जाने के लिए डालटनगंज से रेड़मा व पांकी रोड से जाना पड़ता है. बारालोटा, रजवाडीह होते हुए लेस्लीगंज प्रखंड ऑफिस के बाद धनगांव से पांच किलोमीटर का फासला तय करने पर भकासी गांव मिलेगा. भकासी से 4 किमी की दूरी पर चरइंगीर व कोरीपतरा है और भूख से मौत के लिए चर्चित रहा सीताडीह गांव 2 किमी दूर पर है. यहां अनुसूचित जाति में आनेवाले भुइयां लोगों की आबादी अच्छी-खासी है. झारखंड में देश की तरह करीब एक तिहाई कृषक मजदूर हैं, जबकि झारखंड में 45 फीसदी और भुइयां इनमें सबसे ज्यादा हैं.

43 साल के मोहन भुइयां बताते हैं कि '2003 से इसतिथि बहुते खराब हई. मवेशी खातिर चारा भूसा 4 रु केजी खरीद रहे हैं. पानी के बिना तो सगरो खेती न होइलक. बैल अइसहे पोसाइत हथीं. राशन दुकान से अनाज नइखे मिलइत. घर में अनाज नखवा, तो भंडार कहां से मिलतवा.' गांव वाले कहते हैं कि मनरेगा यहां फेल है. पहले बीपीएल का सर्वे हुआ था, पर वह स्थगित हो गया. यहां वृद्धापेंशन में गड़बड़ी है, जेनरल केटेगरी के कम उम्र के लोगों को फायदा मिल गया है. अभी हाल में सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय खुला है, जहां करीब चालीस बच्चे हैं. देखने से साफ लगता है कि मिडडे मिल के बहाने बच्चों समेत कुछ बेहद बूढ़ों को राहत मिल गयी है. बच्चों को देखने पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस-3) के आंकड़े सही जान पड़ते हैं कि झारखंड में पांच साल से कम उम्र के 57 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं. ऐसे इलाकों में ग्रेड तीन और चार का कुपोषण मिलना आम है. इसी कारण चैनपुर प्रखंड के कांचन गांव में बीते वर्षों में 12 से अधिक बच्चे मर गये.

इसी गांव में 2003 में 19 वर्षीया पातो देवी की भूख से मौत की रपट दर्ज है. तत्कालीन जिला प्रशासन ने इसे झोलाछाप डॉक्टर से इलाज के कारण हुई मौत बताया था. आज पातो की मां राजमती देवी अपने बच्चों व पोतों समेत छह बच्चों को पाल रही है. इनमें पतोहू संजू देवी के मरने के बाद उसके चार बच्चे भी हैं. संसाधनहीनता का स्पष्ट प्रमाण यही है कि पातो के पिता सनिचर भुइयां बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में सरिया सेटिंग के काम के लिए गये हैं. राजमतिया कहती हैं कि 'हमनी के पास बस इहे एकाध कट्ठा जमीन पर घर हइ. न तो खेत हइ अउर न खूंटा गाड़ी. 1982-83 में परचा मिलल रहे, पर अबो ना जमीन हमर होइल. पातो के सादी में इहो रेहन रखा गइलक. का करूं, कइसहूं हाड़-मांस बचल ह सरीर के इहे काफी हव.'

भकासी दरअसल राजहारा पंचायत का हिस्सा है. हरिजन टोला के करीब 120 परिवारों के अलावा दूसरे टोले में उच्च व मध्य जाति के लोग रहते हैं. आगे नवडीहा टोला है, जहां बाभन, भूमिहार आदि रहते हैं. भुइया टोली की बदहाल स्थिति और खेती लायक जमीनों के मालिकाना आदि से वहां पसरी असमानता, संपन्न जातियों का एकाधिकार और कृषि सामंतवाद साफ दिखता है. 26 साल के अजय भुइयां बताते हैं कि गांव में दो हरिजन ही मैट्रिक पास हैं. वह साल में तीन चार-बार करबंदिया पत्थर तोड़ने जाते हैं. 16 साल के मुकेश बताते हैं कि बगल के जंगल से लकड़ी काट कर आजीविका चलाते हैं. अधिकतर घरों में एक-दो सेर अनाज ही है. बीते साल राज्य सरकार ने सूखा राहत में बीपीएल परिवारों को 34 किलो और अंत्योदय परिवारों को 35 किलो राशन मुफ्त राशन देने की घोषणा की. लेकिन भ्रष्ट तंत्र के कारण यह 25-30 किलो ही मिलता है.

इसी गांव में 2003 में 34 साल की कवलपतिया देवी भी भुखमरी का शिकार हुई थी. उनके पति कृष्णा भुइयां माटी काटने जाते हैं. बताते हैं कि 'मनरेगा में साल भर में चारे दिन काम मिलल. बड़ बेटा संतोष छतीसगढ़ कमाये गेल हथी. हम महीना भर से बीमार हीवा और घर में आठ रोज से अनाज के दर्शन ना भइलक'. एक बुजुर्ग ननक राम खुद को अंगरेजी राज में पैदा हुआ बताते हैं. कहते हैं कि 'हमहुं 67 के अकाल देखनी. तब हालत खराब हलई पर मदद मिलल रहे. तीन सेर अनाज पर काम मिलल रहे. हमर वृद्धा पेंशन हइ, पर पोस्ट ऑफिस का दौड लगावे पड़इत हव. हमनी के इंदिरा आवास भी नइखे.' आंकड़ों में झारखंड में 46 फीसदी आबादी बीपीएल में आती है, जो राष्ट्रीय औसत 26 से दोगुना के करीब है.

क्षेत्र में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता रामराज बताते है कि 'लेस्लीगंज में अभी कोई फुलटाइम बीडीओ नहीं हैं. बीते लोकसभा चुनाव के बाद से यह स्थिति है. सुखाड़ राहत के नाम पर जो कुछ मामूली चीजें मिलती हैं, उसका लाभ गांव के दबंग उठा ले जाते हैं. अब भी सुखाड़ से निबटने के लिए जलाशय योजनाओं की कमी है. बड़ी परियोजनाओं में मलय जलाशय योजना पर काम के तीस साल हो गये, पर सिचांई का लाभ नहीं मिला.'

(जारी)

(सीएसडीएस के इनक्लूसिव मीडिया फेलोशिप के तहत लिखी गयी रिपोर्ट.)